नवसर्जन संस्कृति
PRGI No. GJHIN/25/A2786
PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD
वर्ष : 01
अंक : 220
दि. 14.05.2026, गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

केरल में सत्ता का नया चेहरा आज होगा तय, कांग्रेस हाईकमान ने मंथन के बाद अंतिम फैसले पर लगाई मुहर

नई दिल्ली। केरल की राजनीति में लंबे समय से चल रहा मुख्यमंत्री पद का सस्पेंस अब आखिरकार खत्म होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आज राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का आधिकारिक एलान करेगी। कई दिनों तक चली बैठकों, रणनीतिक चर्चाओं और संगठनात्मक मंथन के बाद पार्टी नेतृत्व अंतिम निर्णय पर पहुंच चुका है। कांग्रेस महासचिव Jairam Ramesh ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चयन को लेकर सभी आवश्यक विचार-विमर्श पूरे कर लिए गए हैं और अब अंतिम घोषणा कल सार्वजनिक रूप से की जाएगी। इस ऐलान के साथ ही केरल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत होने की संभावना जताई जा रही है।

कांग्रेस नेतृत्व के अनुसार, मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया केवल राजनीतिक समीकरणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि संगठनात्मक संतुलन, जनभावना, भविष्य की रणनीति और गठबंधन की एकजुटता जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार हाईकमान किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना चाहता था, क्योंकि हालिया विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद कांग्रेस और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) के सामने राज्य में स्थिर और प्रभावी शासन देने की बड़ी जिम्मेदारी है।

केरल कांग्रेस विधायक दल यानी सीएलपी की मंजूरी के बाद अब पूरा फैसला कांग्रेस हाईकमान के हाथ में था। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने लगातार कई दौर की बैठकों में संभावित नामों पर चर्चा की। कांग्रेस का कहना है कि सभी वरिष्ठ नेताओं और संगठन से जुड़े अनुभवी चेहरों से राय लेने के बाद ही अंतिम सहमति बनाई गई है। पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि मुख्यमंत्री चयन के बाद किसी प्रकार की नाराजगी या गुटबाजी सामने न आए।

मुख्यमंत्री पद की दौड़ में तीन बड़े नाम सबसे अधिक चर्चा में रहे। इनमें वरिष्ठ

कांग्रेस नेता Ramesh Chennithala, विपक्ष के प्रमुख चेहरे V. D. Satheesan और एआईसीसी महासचिव K. C. Venugopal शामिल हैं। इन तीनों नेताओं का राज्य की राजनीति में मजबूत प्रभाव माना जाता है और पार्टी संगठन में भी इनकी अलग-अलग पकड़ है। यही वजह रही कि अंतिम निर्णय तक पहुंचने में कांग्रेस नेतृत्व ने काफी सतर्कता बरती।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने केरल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। राहुल गांधी ने वीएम सुधीरन, एमएम हसन और के सुधाकरण समेत आठ पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से वन-टू-वन चर्चा कर राज्य की राजनीतिक स्थिति, संगठनात्मक संतुलन और जनता की अपेक्षाओं पर राय ली। वहीं वरिष्ठ नेता मुल्लापल्ली रामचंद्रन से फोन पर बातचीत कर उनकी राय जानी गई। कांग्रेस नेतृत्व यह समझने की कोशिश कर रहा था कि मुख्यमंत्री का ऐसा चेहरा सामने आए जो न केवल संगठन को एकजुट रख सके बल्कि जनता के बीच भी मजबूत स्वीकार्यता रखता हो।

दिल्ली में पिछले कई दिनों से बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। मंगलवार को राहुल गांधी ने दिल्ली में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के पूर्व अध्यक्षों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों, चुनावी नतीजों और आने वाले समय की चुनौतियों पर विचार किया गया। वरिष्ठ नेता वीएम सुधीरन ने बैठक के बाद कहा कि पार्टी को ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो जनता की भावना और राज्य के हितों के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि केरल की जनता ने यूडीएफ को भारी जनादेश दिया है, इसलिए सरकार गठन में भी परिपक्वता और दूरदृष्टि दिखाई जानी चाहिए।

कांग्रेस नेतृत्व की सबसे बड़ी चिंता यह रही कि मुख्यमंत्री चयन का फैसला कहीं संगठन के भीतर असंतोष या शक्ति संघर्ष का कारण न बन जाए। पार्टी सूत्रों के अनुसार, हाईकमान ने इस बार बेहद संतुलित रणनीति अपनाई है ताकि किसी भी गुट को उपेक्षित महसूस न हो। यही कारण है कि निर्णय में अपेक्षा से अधिक समय लगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस इस बार केरल में स्थायी और मजबूत सरकार देने की तैयारी में है, क्योंकि लंबे समय बाद पार्टी को राज्य में इतना बड़ा जनादेश मिला है।

गौरतलब है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में यूडीएफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 140 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटें जीत लीं। यह जीत केवल चुनावी सफलता नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे केरल की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। कांग्रेस के खाते में 63 सीटें आईं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) को 22 सीटें मिलीं। केरल कांग्रेस ने आठ और आरएसपी ने तीन सीटों पर जीत दर्ज की। इस दो-तिहाई बहुमत ने यूडीएफ को राज्य में बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है।

चार मई को चुनाव परिणाम आने के बाद से ही मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। शुरुआत में माना जा रहा था कि कांग्रेस जल्द फैसला ले लेगी, लेकिन जैसे-जैसे अलग-अलग गुटों की सक्रियता बढ़ी, हाईकमान ने व्यापक सहमति बनाने पर जोर दिया। पार्टी नेतृत्व इस बात को लेकर भी सतर्क रहा कि मुख्यमंत्री का चयन केवल राजनीतिक समीकरणों के आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक क्षमता और भविष्य की नेतृत्व संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाए।

राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा रही कि कांग्रेस इस बार केरल में पीढ़ीगत बदलाव और अनुभवी नेतृत्व के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर सकती है। एक ओर रमेश चेन्निथला जैसे अनुभवी नेता हैं, जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक पकड़ मजबूत मानी जाती है। दूसरी ओर वीडी सतीशन को आक्रामक विपक्षी नेता और नए दौर के प्रभावशाली चेहरे के रूप में देखा जाता है। वहीं केसी वेणुगोपाल का केंद्रीय नेतृत्व के साथ मजबूत समन्वय और संगठनात्मक अनुभव उन्हें भी मजबूत दावेदार बनाता है।

इस पूरे घटनाक्रम ने केरल की राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना दिया है। कांग्रेस के लिए यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि दक्षिण भारत में पार्टी अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक के बाद केरल में बड़ी जीत ने कांग्रेस को नई ऊर्जा दी है और पार्टी इस अवसर को लंबे समय तक राजनीतिक मजबूती में बदलना चाहती है।

अब थानों में हर गतिविधि पर होगी नजर: एंट्री गेट से लॉकअप तक सीसीटीवी निगरानी, सुप्रीम कोर्ट ने जताई संतुष्टि

नई दिल्ली। देशभर के पुलिस थानों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संतोष व्यक्त किया। अदालत को बताया गया कि देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है और बड़ी संख्या में थानों में यह व्यवस्था पूरी भी की जा चुकी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि जिन राज्यों ने फंड की कमी का मुद्दा उठाया है, उनकी सहायता के लिए केंद्र सरकार सकारात्मक रुख अपना सकती है।

यह मामला पुलिस स्टेशनों में कार्यरत सीसीटीवी कैमरों की कमी और मानवाधिकार संरक्षण से जुड़ी एक सुओ मोटू याचिका से संबंधित है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पिछले कई वर्षों से लगातार निगरानी बनाए हुए है। अदालत का मानना रहा है कि पुलिस थानों में आधुनिक निगरानी व्यवस्था केवल सुरक्षा का विषय नहीं है, बल्कि यह नागरिक अधिकारों की रक्षा और पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह देखकर संतोष होता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस दिशा में गंभीरता से काम किया जा रहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस थानों में सीसीटीवी व्यवस्था को लेकर पहले दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन होना चाहिए, ताकि भविष्य में हिरासत में प्रताड़ना, मानवाधिकार उल्लंघन और पुलिस कार्यवाही को लेकर उठने वाले विवादों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके।

मामले में अदालत की सहायता कर रहे अमिकी क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 28 अप्रैल के आदेश के बाद 6 मई को केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में पुलिस थानों में सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की प्रगति, फंडिंग की स्थिति और तकनीकी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसकी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी गई है। सिद्धार्थ दवे ने अदालत को बताया कि कई राज्यों ने सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, डेटा स्टोरेज और तकनीकी रखरखाव के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है। कुछ राज्यों का कहना है कि सीमित बजट और तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण कार्य में देरी हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार इस दिशा में राज्यों की मांगों पर विचार कर रही है और फंड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर काम जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर आगे और चर्चा की आवश्यकता है, जिसके लिए जून या जुलाई में एक और समन्वय बैठक प्रस्तावित की गई है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पुलिस स्टेशनों में केवल औपचारिक रूप से कैमरे लगाने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी निगरानी प्रणाली प्रभावी और कार्यशील होनी चाहिए। अदालत ने पहले दिए गए निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। इसके अलावा लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया और पूछताछ कक्ष जैसे संवेदनशील हिस्सों को भी निगरानी के दायरे में लाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कैमरों में नाइट विजन सुविधा होना अनिवार्य है, ताकि रात के समय भी गतिविधियों की स्पष्ट रिकॉर्डिंग हो सके। साथ ही ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी जरूरी होगी, जिससे किसी भी विवाद या शिकायत की स्थिति में घटनाओं की सटीक जांच की जा सके। अदालत ने डेटा स्टोरेज को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि रिकॉर्डिंग कम से कम एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियां या अदालतें उसे देख सकें।

दरअसल पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने का मुद्दा लंबे समय से मानवाधिकार संगठनों और न्यायपालिका की चिंता का विषय रहा है। हिरासत में मौत, पुलिस प्रताड़ना, अवैध पूछताछ और मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में सख्त रुख अपनाया था। अदालत ने वर्ष 2018 में ऐतिहासिक आदेश देते हुए देश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। कोर्ट का मानना था कि इससे पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और आम नागरिकों का भरोसा मजबूत होगा। इसके बाद दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का दायरा और बढ़ाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालयों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि केवल राज्य पुलिस ही नहीं, बल्कि सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ED), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और अन्य जांच एजेंसियों के कार्यालयों में भी निगरानी व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी जांच प्रक्रिया के दौरान नागरिक अधिकारों का उल्लंघन न हो और जवाबदेही बनी रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस थानों में आधुनिक निगरानी प्रणाली लागू होने से कई स्तरों पर बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे पुलिस कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी होगी, हिरासत में हिंसा और गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और शिकायतों की निष्पक्ष जांच आसान होगी। वहीं दूसरी ओर पुलिसकर्मियों को भी झूठे आरोपों से सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि हर गतिविधि रिकॉर्ड के रूप में उपलब्ध रहेगी।

ज्योतिषी की नियुक्ति पर घिरी तमिलनाडु सरकार, चौतरफा विरोध के बाद विजय ने वापस लिया फैसला

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद उस समय खड़ा हो गया, जब मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार ने उनके करीबी माने जाने वाले ज्योतिषी रिकी राधन पंडित को विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) नियुक्त कर दिया। सरकार का यह फैसला सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। विपक्षी दलों ने इसे प्रशासनिक मर्यादाओं और तर्कसंगत शासन व्यवस्था के खिलाफ बताते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बढ़ते राजनीतिक दबाव, सोशल मीडिया पर उठते सवालों और विधानसभा में हुए हंगामे के बाद आखिरकार विजय सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। नियुक्ति के महज एक दिन बाद ही सरकार ने रिकी राधन पंडित की ओएसडी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया।

तमिलनाडु सरकार के प्रधान सचिव की ओर से 13 मई को जारी आदेश में कहा गया कि रिकी राधन पंडित की विशेष कार्याधिकारी के रूप में नियुक्ति वापस ली जाती है। इस फैसले ने यह साफ संकेत दे दिया कि सरकार बढ़ते विवाद को लंबा नहीं खींचना चाहती थी। हालांकि विपक्ष इसे सरकार की "राजनीतिक मजबूरी" और "जनदबाव के आगे झुकना" बता रहा है।

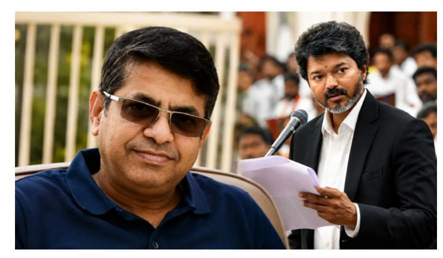

रिकी राधन पंडित केवल एक ज्योतिषी के रूप में ही नहीं, बल्कि टीवीके पार्टी के सक्रिय प्रवक्ता और मुख्यमंत्री विजय के करीबी सहयोगी के रूप में भी जाने जाते हैं। चुनाव अभियान के दौरान वे लगातार विजय के साथ दिखाई दिए थे और पार्टी के भीतर उनकी पहुंच को काफी प्रभावशाली माना जाता रहा है। यही कारण था कि जब उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में ओएसडी जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया, तो राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे कि क्या सरकार प्रशासनिक अनुभव से ज्यादा व्यक्तिगत विश्वास को प्राथमिकता दे रही है।

विपक्षी दलों ने इस नियुक्ति को मुद्दा बनाते हुए सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए। एआईएडीएमके के राज्यसभा सांसद आईएस इनबदुरई ने सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए लिखा कि "जो व्यक्ति दूसरों का भविष्य बताता है, वह अपनी नियुक्ति का भविष्य नहीं देख पाया।" उन्होंने इसे विजय सरकार के "बुरे दिनों की शुरुआत" करार दिया। एआईएडीएमके नेताओं का कहना था कि राज्य जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक ढांचे में नियुक्तियां योग्यता और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत आस्था के आधार पर।

डीएमके ने भी इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। पार्टी प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि एक ज्योतिषी का काम भविष्यवाणी करना हो सकता है, लेकिन सरकार चलाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था, प्रशासनिक प्रक्रिया और नीति निर्माण की समझ जरूरी होती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी और अनुभवी अधिकारियों से ज्यादा भरोसा ज्योतिष पर है। डीएमके नेताओं ने इसे तमिलनाडु की तर्कवादी राजनीति और सामाजिक न्याय की परंपरा के खिलाफ बताया। तमिलनाडु लंबे समय से द्रविड़ राजनीति और तर्कवादी विचारधारा का केंद्र माना जाता रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय जैसे संवेदनशील प्रशासनिक ढांचे में एक ज्योतिषी की नियुक्ति ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। विपक्षी दलों का कहना था कि यह फैसला राज्य की उस वैचारिक पहचान के विपरीत है, जिसमें वैज्ञानिक सोच और प्रशासनिक पारदर्शिता को महत्व दिया जाता है। यह मुद्दा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विधानसभा के भीतर भी इसका असर दिखाई दिया। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों ने इस नियुक्ति को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। डीएमके के सहयोगी दल एमजेके के अध्यक्ष और विधायक थमीमुन अंसारी ने कहा कि व्यक्तिगत आस्था हर व्यक्ति का निजी विषय हो सकता है, लेकिन उसे सरकारी प्रशासन और निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार में "ज्योतिष के फार्मूले" नहीं चल सकते और प्रशासनिक व्यवस्था को तर्क और नियमों के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। डीएमडीके की महासचिव प्रेमलता विजयकांत ने भी इस नियुक्ति की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को जनता की समस्याओं और प्रशासनिक चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए, न कि विवादित नियुक्तियों के जरिए राजनीतिक संदेश देने चाहिए।

सूरत की कपड़ा फैक्टरी से मुक्त कराए गए 91 नन्हें बाल मजदूर, सबसे छोटा महज 7 साल का

सरकार, प्रशासन व नागरिक समाज संगठनों की छापे की एक साझा कार्रवाई में ट्रैफिकिंग के जरिए लाए गए और सूरत की एक कपड़ा फैक्टरी में मामूली पैसों पर खटाए जा रहे 91 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। मुक्त कराए गए इन बच्चों की उम्र सात से 14 के बीच है। हालांकि भनक लगते ही सभी ट्रैफिकर और फैक्टरी मालिक मौके से फरार हो गए। मुक्त कराए गए बच्चों में से ज्यादातर राजस्थान के जनजातीय इलाकों के हैं जबकि तीन उत्तर प्रदेश के और एक-एक बच्चे झारखंड व बिहार के हैं। इन सभी को बाल कल्याण समिति, सूरत के समक्ष पेश किया गया और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

गायत्री सेवा संस्थान (जीएसएस) की छानबीन के आधार पर हुई छापे की इस कार्रवाई में जीएसएस सहित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, राजस्थान के 22 पुलिस अफसरों, सूरत के पूना थाने के अफसरों के साथ नागरिक समाज संगठन एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन (एवीए) भी शामिल था। एवीए और जीएसएस देश में बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के काम कर रहे 250 से भी अधिक नागरिक समाज

संगठनों के देश के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के सहयोगी हैं।

गायत्री सेवा संस्थान महीने भर से सूरत की इस कपड़ा फैक्टरी की निगरानी कर रहा था और छानबीन में यहां बड़ी संख्या में बाल मजदूरों की मौजूदगी की पुष्टि के बाद उसने एनसीपीसीआर को इसकी जानकारी दी। मुक्त कराए बच्चों ने फिर पुलिस को सुराग दिए और उन्हें उन जगहों का पता बताया जहां बाल मजदूरी कराई जा रही थी। गायत्री सेवा संस्थान के निदेशक डॉ. शैलेंद्र पंड्या ने बताया, "बच्चे हमें एक इमारत के पास ले गए जो बाहर से बंद थी। लेकिन उन्होंने बताया कि अंदर बच्चे काम कर रहे हैं। हम जब अंदर गए तो पाया कि वहां सात साल तक के बच्चों से काम कराया जा रहा था। सभी बच्चे घबराए हुए और बदहवासी की हालत में थे और 12 घंटे की शिफ्ट में काम करने के बाद थके हुए थे।"

डॉ. पंड्या ने बताया कि अंदर जाने के बाद वे बच्चों की बदहाली देखकर दंग रह गए। आठ साल के एक बच्चे के पास पहनने को शर्ट तक नहीं थी। वह दूसरे बच्चों के पीछे छिप गया और उनसे पूछ रहा था कि क्या कोई थोड़ी देर के लिए अपनी शर्ट उसे दे सकता है। उन्होंने पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस और सभी हितधारकों की त्वरित कार्रवाई और मामले को गंभीरता से लेने के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को मुक्त करा पाना संभव हो पाया।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इन बाल दुर्व्यापारियों और फैक्टरी मालिकों ने संदेह से बचने के लिए तमाम तरीके अपना रखे थे। छोटे बच्चों को बिल्कुल सुबह यहां लाया जाता था और फिर इमारत के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए जाते थे। शाम को सात बजे काम की शिफ्ट खत्म हो जाने के बाद ही दरवाजे खोले जाते थे। इन सभी बच्चों को आस-पास की कालोनियों में बहुत ही दयनीय और अमानवीय हालत में रखा जाता था। एक छोटे से कमरे में 10 से 12 बच्चे रहते थे जहां बुनियादी सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था। पूछताछ के दौरान कुछ बच्चों ने बताया कि उनके माता-पिता को पता था कि उन्हें मजदूरी के लिए यहां लाया गया है। उधर, ज्यादातर छोटे बच्चों ने बताया कि उन्हें घुमाने के नाम पर यहां लाया गया था और उन्हें कतई अंदाजा नहीं था कि यहां उनसे मजदूरी कराई जाएगी। यह भी पता चला कि कुछ बच्चे इन कपड़ा इकाइयों में तीन-चार साल से काम कर रहे थे जबकि बाकियों को हाल ही में यहां लाया गया था। मुक्त कराए गए बच्चों में आठ और दस साल के दो भाई भी थे जिन्हें राजस्थान के उदयपुर जिले से लाया गया था।

ट्रैफिकिंग गिरोहों और बाल मजदूरी के तार मजबूती से जुड़े होने को रेखांकित करते हुए जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के राष्ट्रीय संयोजक रवि कांत ने कहा, "इस छापे से यह तथ्य स्थापित हो जाता है कि ट्रैफिकिंग गिरोह कितने संगठित हैं और उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। खास तौर से जनजातीय इलाकों और संवेदनशील परिवारों के बच्चों को झूठे वादों के जाल में फंसा कर ऐसी शोषणकारी परिस्थितियों में धकेल दिया जाता है जहां वे बाहरी दुनिया से कट जाते हैं और अपना बचपन खो बैठते हैं। यह मामला एक बार फिर अंतरराज्यीय समन्वय को मजबूत बनाने, बाल मजदूरी की मांग व आपूर्ति पर नजर बनाए रखने, बच्चों का शोषण करने वाले नियोक्ताओं और शोषण में शामिल सभी बिचौलियों की धरपकड़ और उनकी जवाबदेही तय करने की तत्काल जरूरत को साबित करता है।"

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
जितेंद्र परमार

संपादकीय

नीट परीक्षा रद्द होने से प्रतिभाएं हताश

हमारे तंत्र की नाकामी और परीक्षा तंत्र में भ्रष्टाचारियों की बढ़ती सेंध का ही नतीजा है कि पेपर लीक के बाद नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई। भारत में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिले के लिए तीन मई को परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब पौने तेईस लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। ये परीक्षाएं देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5400 केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। दरअसल, पेपर लीक होने के आरोपों के बाद जांच एजेंसियों की सिफारिश पर परीक्षा रद्द की गई है। केंद्र सरकार ने कथित रूप से डेटा लीक और धांधली की व्यापक जांच के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि व्यवस्था में विश्वास बहाली के लिए फिर से परीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। कहा जा रहा है कि एनटीए ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा निष्कर्षों की प्रारंभिक जांच के आधार पर परीक्षा स्थगन का फैसला लिया। निस्संदेह, इस फैसले ने उन लाखों छात्रों को निराश ही किया है जो महीनों से परीक्षा की तैयारी में लगे थे। अब उन्हें नये सिरे से परीक्षा की तैयारी करनी होगी। नीट प्रवेश परीक्षा स्थगित किए जाने के बाद तमाम विपक्षी दलों ने एनटीए व केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोले हैं। कहा जा रहा है कि एनटीए में सुधार नहीं, अब पूरी संरचना बदलने की जरूरत है। एक संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा जा रहा है कि एनटीए के बुनियादी पुनर्गठन की जरूरत है। राजनेता पीपर लीक व प्रश्नपत्रों में गलती सामने आने को छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बता रहे हैं। साथ ही पूरी परीक्षा प्रणाली को बदलने की मांग की जा रही है। साथ ही एनटीए के उद्देश्य और कार्यक्षमता को लेकर शंका जतायी जा रही है।

वहीं कांग्रेस का आरोप है कि एनटीए द्वारा आयोजित 14 राष्ट्रीय परीक्षाओं में से पांच में पेपर लीक और अनियमितताओं के मामले उजागर हुए हैं। इनमें जेईई मेन्स 2025 उत्तर कुंजी के दोषपूर्ण होने पर प्रश्नपत्र में 12 प्रश्न वापस लेने पड़े थे। मांग है कि एनटीए को केंद्रीयकृत करने के बजाय संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। वहीं एनटीए कह रहा है कि छात्रों को नया आवेदन नहीं करना होगा, न ही कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लगेगा। यह भी कि एनटीए अपने संसाधनों का प्रयोग करके दोबारा परीक्षा आयोजित करेगी। साथ ही एनटीए ने परीक्षा में गड़बड़ी की जवाबदेही स्वीकारी है। दरअसल, आरोप है कि नीट का पेपर 'क्वेश्चन बैंक' के जरिये लीक किया गया, जिसमें फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीन से ज्यादा सवाल थे। जिसमें आधे हूबहू परीक्षा में आए। आशंका है कि सोशल मीडिया के जरिये ये प्रश्नपत्र लाखों तक पहुंचे। हालांकि, इस मामले का खुलासा सीकर से हुआ, लेकिन कहते हैं कि पेपर पहले केरल से एक मई को आया और उसके तार नासिक से लेकर उत्तराखंड तक जुड़े थे। एनटीए ने कहा है कि सात मई की रात एक व्हिसलब्लोअर से उन्हें पेपर लीक की सूचना मिली। बताते हैं कि सीकर के एक पीजी संचालक ने पेपर लीक की सूचना पुलिस को दी। कालांतर में पेपर से जुड़ी ऑनलाइन चैट वायरल हो गई। एनटीए द्वारा जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने के बाद एक दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। यह विडंबना ही है कि भ्रष्टाचार के बाजार में लाखों छात्रों की मेहनत और सपने नीलाम हो रहे हैं। कुछ लोग लीक मामलों में राजनीतिक संरक्षण के भी आरोप लगा रहे हैं। तभी कई बार नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के बावजूद किसी को बड़ी सजा अब तक नहीं मिली है। यही वजह कि नीट परीक्षा को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की मांग की जा रही है क्योंकि पेन-पेपर मोड में पेपर लीक होने की ज्यादा आशंका रहती है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा को सुरक्षित व पारदर्शी बताया जा रहा है। साथ ही पारदर्शी जांच व जवाबदेही तय करने की बात कही गई है। सवाल स्टाफ की आउटसोर्सिंग को लेकर भी उठे हैं। परीक्षाएं हाइब्रिड परीक्षा मॉडल के साथ ऑनलाइन कराने की भी मांग है।

ईरानी विमानों को अपने यहाँ छिपा कर पाकिस्तान ने उतार दिया 1971 का कर्ज

> "पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया है कि इस तरह के दावे वास्तविकता से परे हैं, क्योंकि नूर खान वायुसेना अड्डा राजधानी के अत्यंत व्यस्त और आबादी वाले हिस्से में स्थित है। पाकिस्तान का कहना है कि वहां किसी भी बड़े सैन्य बेडे या विमानों को छिपाकर रखना संभव ही नहीं है।

1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब भारतीय हमलों से बचाने के लिए ईरान ने पाकिस्तानी सैन्य विमानों और संसाधनों को सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराया था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि पांच दशक बाद पाकिस्तान उसी एहसान का बदला चुकाता दिखाई देगा। अब आरोप लग रहे हैं कि अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई और क्षेत्रीय तनाव के बीच पाकिस्तान ने ईरानी विमानों को अपने सैन्य ठिकानों पर सुरक्षित शरण दी। इस तरह इस्लामाबाद ने तेहरान का पुराना कर्ज तो उतार दिया है लेकिन अब वह खुद संकट में फंसता दिखाई दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की जटिल कूटनीतिक राजनीति को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है।पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया है कि इस तरह के दावे वास्तविकता से परे हैं, क्योंकि नूर खान वायुसेना अड्डा राजधानी के अत्यंत व्यस्त और आबादी वाले हिस्से में स्थित है। पाकिस्तान का कहना है कि वहां किसी भी बड़े सैन्य बेडे या विमानों को छिपाकर रखना संभव ही नहीं है। दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन ने भी अब तक सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान पर कोई सीधा आरोप नहीं लगाया है, जिससे स्थिति और अधिक जटिल दिखाई दे रही है।

सूत्रों के अनुसार ईरान ने संभावित खतरे को देखते हुए अपने कुछ नागरिक विमानों को पड़ोसी अफगानिस्तान की ओर भेजा। अफगान नागरिक उड्डयन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि महान एयर का एक विमान संघर्ष तेज होने से पहले काबुल पहुंचा था और बाद में सुरक्षा कारणों से उसे हेरात स्थानांतरित कर दिया गया। बताया गया कि अफगान क्षेत्र में पाकिस्तानी हवाई हमलों की खबरों के बाद यह आशंका पैदा हो गई थी कि काबुल हवाई अड्डा भी संभावित निशाना बन सकता है।

इन घटनाओं ने दक्षिण एशिया के जानकारों को 1971 के दौर की याद दिला दी है। उस समय शाह मोहम्मद रजा पहलवी के नेतृत्व वाला ईरान पाकिस्तान का प्रमुख समर्थक बनकर सामने आया था। तेहरान ने इस्लामाबाद को हेलिकाप्टर, ईंधन, गोला बारूद और सैन्य उपकरणों के कलपुर्जे उपलब्ध कराए थे। कई रिपोर्टों में यह भी उल्लेख मिलता है कि पाकिस्तान के कुछ सैन्य विमानों ने ईरानी वायुसेना अड्डों पर शरण ली थी।

बाद में सार्वजनिक हुए अमेरिकी दस्तावेजों से पता चला था कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन प्रशासन ने पर्दे के पीछे ईरान को पाकिस्तान की सहायता के लिए प्रोत्साहित किया था। उस दौर में अमेरिका और चीन दोनों ही पाकिस्तान को कमजोर होने से बचाना चाहते थे। शीत युद्ध के समय ईरान और पाकिस्तान दोनों सोवियत विरोधी सैन्य गठबंधन सेन्टो के सदस्य थे और निक्सन प्रशासन इन्हें क्षेत्र में सोवियत प्रभाव को रोकने वाले महत्वपूर्ण साझेदार मानता था।

पांच दशक बाद वैश्विक राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। आज ईरान अमेरिका का प्रमुख पश्चिम एशियाई प्रतिद्वंद्वी माना जाता है, जबकि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में चीन का सबसे करीबी सुरक्षा सहयोगी बन चुका है। चीन ने हाल के समय में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराने में पाकिस्तान की भूमिका की सार्वजनिक सराहना भी की है। इस बदलती परिस्थिति में पाकिस्तान का संतुलन साधना पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है।

पाकिस्तान एक ओर चीनी सैन्य उपकरणों पर अत्यधिक निर्भर है। रिपोर्टों के अनुसार 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान के प्रमुख हथियार आयात का लगभग अस्सी प्रतिशत हिस्सा चीन से आया। वहीं दूसरी ओर इस्लामाबाद अमेरिका के साथ अपने सैन्य और खुफिया संबंधों को फिर से मजबूत करने की कोशिश भी कर रहा है, जो बराक ओबामा प्रशासन के दौरान काफी कमजोर पड़ गए थे।

पाकिस्तानी अधिकारी लगातार यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि तेहरान के साथ उनके संबंध किसी गुप्त सैन्य सहयोग की बजाय क्षेत्रीय स्थिरता के लिए रचनात्मक कूटनीति का हिस्सा हैं। पाकिस्तान समय समय पर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश भी करता रहा है। उसका दावा है कि दोनों देशों के साथ कार्यकारी संबंध बनाए रखने की उसकी क्षमता क्षेत्रीय तनाव कम करने में सहायक हो सकती है।

इसके बावजूद अमेरिकी सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक प्रभावशाली हिस्से में पाकिस्तान को लेकर संदेह अब भी गहराई से मौजूद है। अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी की स्मृति आज भी अमेरिका पाकिस्तान संबंधों पर भारी पड़ती है। अमेरिकी अधिकारी और सांसद लंबे समय से पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के कुछ तत्वों पर इस्लामी उग्रवादी संगठनों के साथ चयनात्मक संबंध रखने के आरोप लगाते रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान इन आरोपों को लगातार नकारता आया है।

ताजा आरोपों ने अमेरिकी संसद में भी नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने चेतावनी दी है कि यदि पाकिस्तान द्वारा ईरान को सैन्य सहायता या शरण देने की खबरें सही साबित होती हैं, तो अमेरिका को ईरान और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ के रूप में इस्लामाबाद की भूमिका का पूरी तरह पुनर्मूल्यांकन करना पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की राजनीति में पुराने रिश्ते, सामरिक हित और बदलते वैश्विक गठबंधन आज भी गहराई से प्रभाव डाल रहे हैं।

बहरहाल, विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान पर आंख मूंदकर भरोसा करना अमेरिका सहित कई देशों के लिए पहले भी भारी पड़ चुका है। हाल के वर्षों में अमेरिकी रणनीतिक और सुरक्षा रिपोर्टों में भी यह संकेत दिया गया था कि पाकिस्तान की नीतियां भविष्य में अमेरिका के लिए प्रत्यक्ष चुनौती बन सकती हैं। कुछ विश्लेषणों में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा गया है जिनके फैसले क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ा सकते हैं और अमेरिकी हितों के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। यही कारण है कि वाशिंगटन में यह राय मजबूत होती जा रही है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी सामरिक या कूटनीतिक साझेदारी में अमेरिका को अत्यंत सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी।

प्रेरणा

खुशी का रहस्य बाहर नहीं, भीतर छिपा है

दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो खुश नहीं रहना चाहता। हर इंसान अपने जीवन में सुख, शांति और संतोष की तलाश करता है। कोई धन कमाकर खुशी ढूंढता है, कोई प्रसिद्धि में, तो कोई शक्ति और अधिकार में। लेकिन जीवन का एक गहरा सच यह भी है कि बाहरी उपलब्धियां हमेशा भीतर की शांति नहीं दे पातीं। आज इंसान पहले से ज्यादा सुविधाओं से घिरा हुआ है, फिर भी उसके भीतर बेचैनी, तनाव और खालीपन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण केवल इतना है कि उसने खुशी को गलत जगह तलाशना शुरू कर दिया है। वह यह भूल गया है कि असली आनंद वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में छिपा होता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन इसी सत्य की एक सुंदर मिसाल है। दुनिया उन्हें विज्ञान का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति मानती थी। उनके सिद्धांतों ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। सम्मान, प्रसिद्धि और धन उनके पास किसी कमी की तरह नहीं थे। लेकिन फिर भी उनका जीवन आश्चर्यजनक रूप से सरल था। उनका कमरा साधारण था, जीवन में दिखावा नहीं था और चेहरे पर एक शांत मुस्कान रहती थी। वे उन लोगों में से नहीं थे जो हर समय और ज्यादा पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। उन्होंने जीवन को केवल सफलता से नहीं, बल्कि संतोष से भी समझा था।

एक दिन एक धनी उद्योगपति उनसे मिलने पहुंचा। उसने आइंस्टीन का सादा जीवन देखा तो हैरान रह गया। उसने कहा, "प्रोफेसर, आपके पास इतना नाम और सम्मान है। यदि आप चाहें तो इससे कई गुना ज्यादा धन कमा सकते हैं। फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते?" यह सवाल केवल उस उद्योगपति का नहीं था, बल्कि आज के समाज की मानसिकता का प्रतीक था। हम अक्सर मान लेते हैं कि अधिक पैसा और अधिक सुविधाएं ही जीवन का अंतिम लक्ष्य हैं। लेकिन आइंस्टीन ने उसका जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि एक दृश्य से दिया।

वे उसे खिड़की के पास ले गए। बाहर एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा था। हवा कभी पतंग को ऊपर ले जाती, कभी नीचे गिरा देती, लेकिन बच्चा हर स्थिति में मुस्कुरा रहा था। वह हवा को नियंत्रित नहीं कर सकता था, फिर भी उसका आनंद ले रहा था। आइंस्टीन ने उद्योगपति से कहा, "जीवन भी ऐसा ही है। यदि इंसान हर चीज को नियंत्रित करने और लगातार ज्यादा पाने की कोशिश में ही लगा रहे, तो वह जीने का आनंद खो देता है।" यही जीवन का सबसे बड़ा दर्शन है। खुशी नियंत्रण में नहीं, स्वीकार करने में है। आनंद संग्रह करने में नहीं, अनुभव करने में है।

आज का समाज तुलना के जाल में फंस चुका है। लोग अपनी खुशियों को दूसरों की उपलब्धियों से मापने लगे हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, तो दूसरा परेशान हो जाता है। कोई विदेश घूमने चला गया, तो किसी को अपना जीवन फीका लगने लगता है। सोशल मीडिया ने इस मानसिकता को और गहरा कर दिया है। लोग दूसरों के जीवन की चमक देखकर यह मान लेते हैं कि वे खुद पीछे छूट गए हैं। धीरे-धीरे इंसान अपनी वास्तविक खुशियों को भूल जाता है और ऐसी दौड़ में शामिल हो जाता है जिसका कोई अंत नहीं।

असल में इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होतीं। एक इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी जन्म ले लेती है। यही कारण है कि केवल बाहरी चीजों के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाता। उसके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहता है। दूसरी ओर, संतोष रखने वाला व्यक्ति छोटी-छोटी बातों में भी आनंद महसूस कर लेता है। उसे परिवार के साथ बैठना अच्छा लगता है, प्रकृति की सुंदरता सुकून देती है और साधारण पल भी उसके लिए खास बन जाते हैं।

संतोष का अर्थ यह नहीं कि इंसान महत्वाकांक्षी न रहे। इसका मतलब यह भी नहीं कि वह मेहनत करना छोड़ दे। संतोष का असली अर्थ है—जो हमारे पास है, उसकी कीमत समझना। इंसान अपने सपनों की ओर बढ़े, सफलता प्राप्त करे, लेकिन अपनी खुशी को केवल भविष्य पर निर्भर न करे। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा यह सोचता रहता है कि "जब मुझे यह मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा," वह कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। उसका जीवन हमेशा इंतजार में गुजर जाता है।

हमारे पूर्वजों और संतों ने हमेशा सादगी और संतोष को सबसे बड़ी संपत्ति माना। उन्होंने कहा कि धन से घर खरीदा जा सकता है, लेकिन शांति नहीं। महंगे बिस्तर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन नींद नहीं। प्रसिद्धि खरीदी जा सकती है, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं। यही कारण है कि दुनिया के कई सबसे सफल लोग भी भीतर से अकेले और परेशान दिखाई देते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, फिर भी मन खाली रहता है। वहीं एक साधारण किसान, मजदूर या शिक्षक, जिसके पास सीमित साधन हैं लेकिन मन में संतोष है, वह अधिक खुश दिखाई देता है।

प्रकृति भी हर पल हमें यही संदेश देती है। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, फिर भी देते रहते हैं। नदी बिना रुके बहती रहती है, क्योंकि उसका आनंद बहने में है। सूरज हर दिन बिना किसी अपेक्षा के रोशनी देता है। प्रकृति कहीं भी लालच नहीं सिखाती। लेकिन इंसान ने अपनी जरूरतों को इतना बढ़ा लिया है कि अब उसे शांति भी एक उपलब्धि की तरह चाहिए। वह हर चीज जल्दी चाहता है और हर समय आगे निकलना चाहता है। यही जल्दबाजी उसके भीतर का संतुलन खत्म कर देती है।

जीवन का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब इंसान वर्तमान को स्वीकार करना सीख लेता है। जब वह यह समझ जाता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, फिर भी जीवन खूबसूरत हो सकता है। खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी उपलब्धियों की जरूरत नहीं होती। कई बार एक सच्ची मुस्कान, अपनों का साथ, शाम की ठंडी हवा या मन की शांति ही सबसे बड़ी खुशी बन जाती है।

आइंस्टीन ने केवल विज्ञान को नहीं समझा था, उन्होंने जीवन को भी गहराई से समझा था। उन्होंने जाना कि महानता और खुशी दो अलग चीजें हैं। इंसान महान बन सकता है, लेकिन यदि उसके भीतर संतोष नहीं है तो वह कभी सच में खुश नहीं रह सकता। जीवन का असली आनंद सब कुछ पकड़ लेने में नहीं, बल्कि कुछ चीजों को छोड़ देने में भी है। जब इंसान यह सीख जाता है कि हर इच्छा जरूरी नहीं होती और हर उपलब्धि ही खुशी नहीं देती, तभी वह भीतर से हल्का महसूस करता है।

अंततः जीवन की सबसे बड़ी दौलत संतोष ही है। क्योंकि यही वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। यही वह रोशनी है जो भीतर शांति पैदा करती है। और यही वह एहसास है जो हमें सिखाता है कि खुशी बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर छिपी हुई है।

योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार, भाजपा नेतृत्व की मंशानुरूप करेगा 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की नैय्या पार?

राजनीतिक गुणा-भाग व विधानसभा चुनावों के चलते उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से लंबित चले आ रहे यूपी कैबिनेट के विस्तार पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की आखिरकार मौहर लग ही गई। जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज़ हो गयी थी। शनिवार शाम 9 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के बाद से ही कैबिनेट विस्तार में शामिल होने वाले चहरों के वारे में राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह के कयास लगाये जा रहे थे। वहीं लखनऊ स्थित जन भवन में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी शासन-प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार 10 मई 2026 की दोपहर 3.30 बजे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 6 नये चहरों भूपेंद्र चौधरी व मनोज पांडेय को कैबिनेट मंत्री, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेन्द्र दिलेर व हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया, वहीं अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर का कद बढ़ाते हुए उन्हें राज्य मंत्री की जगह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। हालांकि यूपी कैबिनेट विस्तार में कई पुराने चेहरों को हटाकर के कुछ नये चहरों को शामिल करने की देश व प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा चल रही थी, राजनेताओं व राजनीतिक विश्लेषकों की यूपी कैबिनेट विस्तार कि लिस्ट पर निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन जब लिस्ट सामने आई तो किसी भी पुराने चेहरों को मंत्रीमंडल से हटाएं बिना ही 6 नये चहरों को मंत्रीमंडल में शामिल किया गया और दो राज्य मंत्रियों का प्रमोशन करते हुए उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना दिया गया। हालांकि सूत्रों के अनुसार इस यूपी कैबिनेट विस्तार में कुछ चर्चित चेहरों के नाम अंतिम समय में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के राजनीतिक गुणा-भाग की कसौटी पर खरा उतरने में विफल रहे, जिसके चलते अंतिम समय में उनके नाम कैबिनेट विस्तार की राज्यपाल के पास जाने वाली लिस्ट में बाहर हो गये।

इस कैबिनेट विस्तार में शामिल राजनेताओं के प्रोफाइल पर संक्षिप्त नज़र डालें तो कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी वर्ष 2017-2022 वाली योगी सरकार में भी पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं और वह भाजपा के निवर्तमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वह राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी और बड़े जाट नेता के रूप में स्थापित माने जाते हैं। वहीं तेजतर्रार, व्यवहार कुशल, दबंग विधायक मनोज पांडेय ब्राह्मण समाज से आते हैं, वह रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं, वह सपा की अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने राज्यसभा के चुनावों में खुलकर के भाजपा प्रत्याशी का साथ दिया था, जिसके बाद उन्हें सपा से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाकर के ईनाम दिया गया है। उनकी ताजपोशी से भाजपा के नेतृत्व स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भाजपा सहयोग करने वालों का हमेशा ध्यान रखती है।

मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर गूर्जर समाज से आते हैं, डॉक्टर तोमर सरल स्वभाव के शानदार राजनेता हैं, फिलहाल वह योगी सरकार में राज्य मंत्री ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत का कार्यभार देख रहे हैं, कैबिनेट विस्तार में उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ दिलाई गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव निरंतर गूर्जर वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर तोमर के प्रमोशन को गूर्जर वोटरों को साधने की भाजपा नेतृत्व की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

वहीं कानपुर देहात के सिकंदरा से भाजपा के विधायक अजीत पाल फिलहाल योगी सरकार में राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का कार्य देख रहे हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उनका प्रमोशन करते हुए उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद की शपथ दिलाई है।

वहीं कैबिनेट विस्तार में शामिल राज्य मंत्रियों की बात करें तो कन्नौज के तिर्वा से विधायक विधायक कैलाश सिंह राजपूत, वाराणसी में भाजपा के जिलाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, अलीगढ़ के खैर से भाजपा के विधायक सुरेंद्र दिलेर, फतेहपुर के खागा से भाजपा की विधायक कृष्णा पासवान ने पहली बार राज्यमंत्री के रूप में पद व गोपनीयता की शपथ ली है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को योगी सरकार के इस कैबिनेट विस्तार से बहुत उम्मीदें हैं।

हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के कोर वोटर माने जाने वाले त्यागी समाज के हाथ इस बार के कैबिनेट विस्तार में भी खाली ही रहे, जबकि त्यागी समाज के एक मात्र विधायक अजीत पाल त्यागी व विधान परिषद सदस्य अश्विनी त्यागी दोनों में से कम से कम एक का नाम कैबिनेट विस्तार की इस लिस्ट में शामिल होने की उम्मीद की जा रही थी।

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट विस्तार का लक्ष्य वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक, सामाजिक, जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधते हुए योगी सरकार के पक्ष में जबरदस्त उत्साहपूर्ण माहौल बनाने का है। वहीं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूला तोड़ करते हुए योगी सरकार के पक्ष में ब्राह्मण, ओबीसी, दलित व अन्य सभी सनातनियों को एकजुट करना है। हालांकि यह तो आने वाला समय ही बताएगा की भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इसमें राजनीतिक गुणा-भाग में कितना सफल होगा, लेकिन जनता की अदालत में बार-बार के चुनाव परिणामों से यह स्पष्ट है कि मोदी, शाह व योगी की लोकप्रियता व चाणक्य नीति की काट का अभी देश में विपक्षी दलों के पास कोई विकल्प नहीं है।

अभियान

देवघर की दिव्य महिमा: जहां हर धड़कन में बसते हैं बाबा बैद्यनाथ और मां शक्ति

भारत की आध्यात्मिक परंपरा केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रही, बल्कि यहां के मंदिरों, तीर्थों और धार्मिक स्थलों ने सदियों से लोगों के मन में विश्वास, भक्ति और आत्मिक शक्ति का संचार किया है। इस पवित्र भूमि पर अनेक ऐसे धाम मौजूद हैं, जिनका महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक चेतना के कारण भी अत्यंत विशेष माना जाता है। इन्हीं दिव्य स्थलों में झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम का नाम अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ लिया जाता है। यह धाम केवल भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग नहीं है, बल्कि वह अद्वितीय स्थान भी है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। यही कारण है कि इस पवित्र धाम की महिमा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहां हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं।

भगवान शिव को हिंदू धर्म में संहार और सृजन दोनों का देवता माना गया है। वे योगियों के देव भी हैं और गृहस्थ जीवन के आदर्श भी। शिव की आराधना मनुष्य को भय, दुख और मानसिक अशांति से मुक्ति दिलाती है। धार्मिक मान्यता है कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव स्वयं ज्योति के रूप में विराजमान हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन से भक्तों के जीवन के संकट दूर होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इन बारह ज्योतिर्लिंगों में देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम सबसे अलग और विशेष माना जाता है, क्योंकि यहां केवल शिवलिंग ही नहीं, बल्कि मां शक्ति का पवित्र शक्तिपीठ भी स्थित है।

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव का अपमान किया, तब माता सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकीं। उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। माता सती की मृत्यु से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और शोकग्रस्त हो गए। वे माता सती के शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। उनके इस रौद्र रूप से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां-जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मान्यता है कि देवघर में माता सती का हृदय गिरा था। इसी कारण यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजित हुआ और यहां मां शक्ति का वास माना गया।

यह वही पवित्र भूमि है जहां भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हैं। शिव और शक्ति का यह दिव्य संगम विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि बाबा बैद्यनाथ धाम को आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहां आने वाले भक्त केवल शिव की पूजा नहीं करते, बल्कि मां पार्वती की आराधना भी करते हैं। इस संयुक्त पूजा का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि भारतीय दर्शन में शिव और शक्ति को सृष्टि के दो मूल तत्व माना गया है। शिव चेतना हैं और शक्ति ऊर्जा। दोनों के बिना संसार का संचालन संभव नहीं है।

बाबा बैद्यनाथ धाम को "कामना लिंग" भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यहां जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यही कारण है कि देशभर से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। कोई स्वास्थ्य की कामना लेकर आता है, कोई संतान सुख के लिए, तो कोई मानसिक शांति और समृद्धि की इच्छा लेकर। भक्तों का विश्वास है कि बाबा बैद्यनाथ और मां शक्ति की कृपा से जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं।

इस धाम से जुड़ी रावण की कथा भी अत्यंत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि लंका के राजा रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक शिवलिंग प्रदान किया और कहा कि इसे लंका ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि इसे मार्ग में कहीं भूमि पर मत रखना। यदि ऐसा हुआ तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चला, लेकिन देवताओं ने उसकी योजना को विफल करने के लिए एक लीला रची। मार्ग में रावण को कुछ समय के लिए रुकना पड़ा और उसने एक ग्वाले को शिवलिंग पकड़ने के लिए दिया। अधिक देर तक भार संभाल न पाने के कारण ग्वाले ने शिवलिंग भूमि पर रख दिया। उसी क्षण शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। यही स्थान आज बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है।

देवघर का वातावरण भक्तिमय और अत्यंत आध्यात्मिक माना जाता है। यहां मंदिर की घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और हर-हर महादेव के जयकारे भक्तों के मन में एक अलग प्रकार की ऊर्जा भर देते हैं। विशेष रूप से सावन के महीने में इस धाम की भव्यता देखने लायक होती है। देश के अलग-अलग हिस्सों से लाखों कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। लगभग सौ किलोमीटर से अधिक की यह यात्रा कठिन जरूर होती है, लेकिन भक्तों की आस्था उन्हें थकने नहीं देती। पूरा मार्ग "बोल बम" के जयकारों से गूंज उठता है और वातावरण पूरी तरह शिवमय हो जाता है।

मंदिर परिसर की वास्तुकला भी प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत करती है। मुख्य मंदिर के अलावा यहां कई अन्य देवी-देवताओं के मंदिर भी स्थित हैं। मां पार्वती का मंदिर यहां विशेष महत्व रखता है। एक धार्मिक मान्यता यह भी है कि बाबा बैद्यनाथ और मां पार्वती के मंदिर को एक पवित्र धागे से जोड़ा गया है, जो शिव और शक्ति के अटूट संबंध का प्रतीक माना जाता है। यह दृश्य भक्तों के मन में गहरी श्रद्धा उत्पन्न करता है।

देवघर केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रतीक है। यहां आने वाले श्रद्धालु केवल पूजा करने नहीं आते, बल्कि अपने भीतर की अशांति और तनाव को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर जाते हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में जब मनुष्य मानसिक रूप से थक जाता है, तब ऐसे पवित्र स्थल उसे भीतर से शक्ति प्रदान करते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम का वातावरण मन को शांति देता है और यह एहसास कराता है कि जीवन में भक्ति और विश्वास का कितना महत्व है।

शिव और शक्ति का एक साथ विराजमान होना केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि जीवन दर्शन के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव त्याग, ध्यान और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं, जबकि शक्ति सृजन, ऊर्जा और जीवन की गतिशीलता का स्वरूप हैं। जब दोनों एक साथ होते हैं, तभी संतुलन बनता है। यही संदेश बाबा बैद्यनाथ धाम अपने भक्तों को देता है कि जीवन में संतुलन और समरसता ही वास्तविक सुख का आधार है।

आज भी लाखों लोग इस धाम की महिमा के अनुभव साझा करते हैं। कई श्रद्धालु मानते हैं कि यहां आकर उनकी वर्षों पुरानी मनोकामनाएं पूरी हुईं। कुछ लोगों को मानसिक शांति मिली, तो कुछ को जीवन में नई दिशा। यही कारण है कि इस धाम की लोकप्रियता समय के साथ और बढ़ती जा रही है। यहां केवल भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

बाबा बैद्यनाथ धाम भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की उस गहरी भावना को जीवित रखता है, जिसमें भक्ति केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का माध्यम होती है। यहां शिव और शक्ति की संयुक्त आराधना यह सिखाती है कि जीवन में प्रेम, संतुलन, विश्वास और ऊर्जा का होना कितना आवश्यक है।

देवघर की यह पवित्र भूमि आज भी करोड़ों लोगों के लिए आशा, विश्वास और भक्ति का केंद्र बनी हुई है। यहां पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे मनुष्य सांसारिक चिंताओं से दूर किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर गया हो। मंदिर की आरती, भक्तों की श्रद्धा और शिव-शक्ति की अलौकिक उपस्थिति हर व्यक्ति के मन को भक्ति से भर देती है। यही कारण है कि बाबा बैद्यनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वह दिव्य स्थल है जहां आस्था और अध्यात्म एक साथ जीवंत रूप में दिखाई देते हैं।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

तेल के डिब्बे हुए छोटे, जेब पर बोझ बड़ा: गुजरात में 'श्रिंकफ्लेशन' को लेकर कांग्रेस का सरकार पर तीखा हमला

सूरत। गुजरात में लगातार बढ़ती महंगाई और खाने के तेल की घटती पैकेजिंग को लेकर सियासत तेज हो गई है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी दर्शनकुमार ए. नायक ने राज्य सरकार पर उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बाजार में खाने के तेल को लेकर "श्रिंकफ्लेशन" का खेल खुलेआम चल रहा है, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेल कंपनियां और व्यापारिक समूह पैकेजिंग का वजन कम करके आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं, जबकि कीमतों में किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा रही। कांग्रेस ने इसे सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के साथ आर्थिक अन्याय और बाजार में पारदर्शिता की कमी बताया है।

दर्शनकुमार नायक ने कहा कि गुजरात देश के सबसे बड़े तिलहन उत्पादक राज्यों में गिना जाता है। राज्य में बड़े पैमाने पर मूंगफली और कपास की खेती होती है, जिसके कारण यहां खाद्य तेल उत्पादन की मजबूत व्यवस्था मौजूद है। इसके बावजूद आम लोगों को महंगे दामों पर तेल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य में उत्पादन भरपूर हो रहा है तो फिर बाजार में तेल के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम परिवार पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है और अब तेल कंपनियों द्वारा पैकेजिंग घटाकर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील का स्वागत किया जिसमें लोगों से स्वास्थ्य और आयात खर्च कम करने के लिए खाने के तेल का सीमित उपयोग करने की बात कही गई थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह अपील देशहित और स्वास्थ्य की दृष्टि से सकारात्मक है, लेकिन दूसरी ओर बाजार में जिस तरह से "श्रिंकफ्लेशन" का प्रयोग हो रहा है, वह उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाला और चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कंपनियां पैकेजिंग का वजन कम कर रही हैं, लेकिन कीमतें लगभग पहले जैसी ही रखी जा रही हैं, जिससे ग्राहक बिना जानकारी के अधिक कीमत चुका रहा है।

दर्शनकुमार नायक ने कहा कि कुछ वर्षों पहले तक खाने का तेल आमतौर पर 15 किलो या 15 लीटर के डिब्बों में मिलता था। लेकिन अब अधिकतर कंपनियों ने पैकेजिंग को घटाकर 12.5 किलो, 13 किलो या 13 लीटर कर दिया है। बाजार में पैकेट और डिब्बों का आकार देखने में लगभग पहले जैसा ही रखा गया है, जिससे आम ग्राहक आसानी से यह समझ नहीं पाता कि वास्तविक मात्रा कम कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह तरीका उपभोक्ताओं के साथ पारदर्शिता के सिद्धांत के खिलाफ है और इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सरकार की है।

उन्होंने कहा कि गुजरात में वर्ष 2025-26 के दौरान मूंगफली उत्पादन 46 से 66 लाख मीट्रिक टन के बीच दर्ज किया गया है, जो देश के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक माना जा रहा है। इसके बावजूद बाजार में मूंगफली तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कांग्रेस नेता के अनुसार मूंगफली तेल के एक कैन की कीमत 2341 रुपये से बढ़कर 2719 रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह कपास उत्पादन भी लगभग 92.48 लाख गांठ तक दर्ज किया गया है, लेकिन खाद्य तेल बाजार में इसका लाभ आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्पादन बढ़ने के बावजूद कीमतों में राहत नहीं मिलना यह दर्शाता है कि बाजार में कहीं न कहीं जमाखोरी, कृत्रिम कमी या व्यापारिक गठजोड़ जैसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं।

दर्शनकुमार नायक ने सरकार से कई सीधे सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्पष्ट करे कि 15 किलो और 15 लीटर की पैकेजिंग को घटाकर 12.5 और 13 किलो/लीटर करने की अनुमति किस विभाग या प्राधिकरण ने दी। क्या लीगल मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई थी। यदि पैकेजिंग कम की गई है तो उसी अनुपात में कीमतों में कमी क्यों नहीं लाई गई। उन्होंने कहा कि आम ग्राहक को यह जानने का अधिकार है कि वह जिस कीमत पर सामान खरीद रहा है, उसकी वास्तविक मात्रा कितनी है और प्रति किलो या प्रति लीटर उसे कितना भुगतान करना पड़ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान स्थिति में उपभोक्ता धीरे-धीरे आर्थिक नुकसान झेल रहा है, लेकिन बाजार व्यवस्था इतनी जटिल बना दी गई है कि सामान्य व्यक्ति इस बदलाव को तुरंत समझ नहीं पाता। उन्होंने कहा कि यही "श्रिंकफ्लेशन" की सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें उत्पाद का आकार छोटा कर दिया जाता है लेकिन कीमत लगभग समान रखी जाती है। इससे कंपनियां अपने मुनाफे को सुरक्षित रखती हैं और ग्राहक को वास्तविक बढ़ी हुई कीमत का एहसास भी नहीं हो पाता।

कांग्रेस नेता ने मांग की कि राज्य सरकार इस पूरे मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन करे। उन्होंने कहा कि तेल मिलर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहां छापेमारी कर यह जांच की जानी चाहिए कि कहीं कृत्रिम रूप से स्टॉक रोककर कीमतें तो नहीं बढ़ाई जा रहीं। साथ ही यदि किसी प्रकार की कार्टेलाइजेशन या जमाखोरी सामने आती है तो संबंधित कंपनियों और व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया नियम लागू करे, जिसके तहत खाने के तेल के डिब्बों और पैकेटों पर "पुराना वजन", "नया वजन" और "प्रति किलो या प्रति लीटर वास्तविक कीमत" स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य किया जाए। इससे ग्राहक आसानी से समझ सकेगा कि उत्पाद की मात्रा में कितना बदलाव हुआ है और वह वास्तविक रूप से कितनी कीमत चुका रहा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए यह कदम बेहद जरूरी है।

दर्शनकुमार नायक ने कहा कि गुजरात जैसे उत्पादन सम्पन्न राज्य में यदि आम जनता को महंगे दामों पर कम मात्रा में तेल खरीदना पड़ रहा है तो यह केवल बाजार की समस्या नहीं बल्कि प्रशासनिक विफलता भी है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में रहें और उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार की भ्रामक व्यापारिक नीति न अपनाई जाए।

उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य संबंधी अपील को गंभीरता से लिया है और लोग सीमित तेल उपयोग की दिशा में जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन इसका फायदा कंपनियों को अतिरिक्त मुनाफा कमाने के रूप में नहीं मिलना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी केवल अपील करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि बाजार व्यवस्था निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे।

खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों और घटती पैकेजिंग का मुद्दा अब केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बनता जा रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े उत्पादों में इस प्रकार के बदलाव का सीधा असर मध्यमवर्ग और गरीब परिवारों पर पड़ता है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा गुजरात की राजनीति और बाजार व्यवस्था दोनों में चर्चा का केंद्र बना रह सकता है।

माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने साबरमती रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण

साबरमती स्टेशन से ट्रेन द्वारा दिल्ली के लिए किया प्रस्थान

आज दिनांक 13.05.2026 को गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी ने पुनर्विकसित किए जा रहे साबरमती रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान माननीय राज्यपाल ने साबरमती स्टेशन पर प्रदर्शित लघु मॉडल एवं स्टेशन पुनर्विकास योजना का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने माननीय राज्यपाल को साबरमती रेलवे स्टेशन तथा NHSRCL (बुलेट ट्रेन) स्टेशन परियोजना के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

इस अवसर पर माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज पहली बार उन्हें साबरमती रेलवे स्टेशन देखने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश एवं श्री अन्नु त्यागी द्वारा स्टेशन परियोजना की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसे देखकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित एवं प्रसन्न हैं।

माननीय राज्यपाल ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया बुलेट ट्रेन अभियान तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और विशेष रूप से गुजरात में इसका कार्य अत्यंत प्रभावशाली ढंग से संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से देश के विभिन्न भागों के लिए संचालित हो रही ट्रेनों के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न किए बिना इतना भव्य एवं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना अपने आप में अद्वितीय है तथा संभवतः भारत में पहली बार इस प्रकार का स्टेशन विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि भारत सरकार की कैबिनेट द्वारा आज ही धोलेरा से साबरमती तक सेमी हाई स्पीड ट्रेन परियोजना को लगभग 20,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही अहमदाबाद एवं गांधीनगर क्षेत्र मेट्रो नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है, जिससे यात्रियों को देश के विभिन्न भागों में जाने के लिए उत्कृष्ट एवं निर्बाध कनेक्टिविटी प्राप्त होगी।

माननीय राज्यपाल ने कहा कि साबरमती स्टेशन को अत्यंत व्यवस्थित एवं आधुनिक रूप से विकसित किया जा रहा है, जहां आने वाली एवं जाने वाली ट्रेनों के लिए पृथक व्यवस्था होगी। बुलेट ट्रेन, मेट्रो तथा देश के विभिन्न भागों से आने वाली ट्रेनों का यह संगम भविष्य में एक दर्शनीय केंद्र बनेगा, जिस पर देशवासियों को गर्व एवं स्वाभिमान का अनुभव होगा। उन्होंने इस आधुनिक विकास कार्य के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तथा रेलवे प्रशासन एवं समस्त रेल अधिकारियों को श्रेय दिया।

माननीय राज्यपाल ने कहा कि वे आज रेलमार्ग से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तथा प्रधानमंत्री जी द्वारा देशवासियों से की गई अपील के अनुरूप उन्होंने संकल्प लिया है कि उनकी अधिकांश आगामी यात्राएं रेल एवं एसटी बसों के माध्यम से होंगी। उन्होंने बताया कि वे प्रत्येक सप्ताह गुजरात के विभिन्न तालुकाओं में किसानों के बीच जाते हैं, जनसभाएं करते हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तथा अनुसूचित जाति परिवारों के बीच समय बिताते हैं। अब वे इन यात्राओं को हवाई मार्ग के बजाय रेलवे एवं एसटी बसों के माध्यम से करेंगे। साथ ही उन्होंने अपने काफिले को भी सीमित करते हुए केवल तीन वाहनों तक रखा है, ताकि देश के विकास एवं ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान दे सकें।

चुनाव में महंगे वादे, फिर मितव्ययिता पर उपदेश: नेताओं के बयानों और कार्यों पर सवाल

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। हमारे यहाँ एक कहावत है कि "समझदार व्यक्ति को अपने ससुराल नहीं जाना चाहिए और मूर्ख को यह सिखाया जाना चाहिए कि यदि वह अच्छा ससुर है, तो उसे अपने ससुराल में ही रहना चाहिए।" यह कहावत आज के नेताओं पर कुछ हद तक लागू होती प्रतीत होती है, जिनके शब्द और कार्य अलग हैं।

एक तरफ तो नेता मीडिया की मदद से झूठी लोकप्रियता हासिल करने के झूठे प्रयास में जनता को सूफी उपदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वही नेता बेहिसाब पैसा खर्च करके यह साबित कर रहे हैं कि हमें कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। इस उथल-पुथल भरे कलियुग में, जब जनता दो रुपये का भोजन भी मुश्किल से पा रही है, तब उन्हें बुरी तरह पीटने जैसे "बलिदान" की बात करना कितना उचित है? इसके बावजूद, देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रुपये का लगातार गिरता मूल्य है। लेकिन इसी दौरान पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हुए,

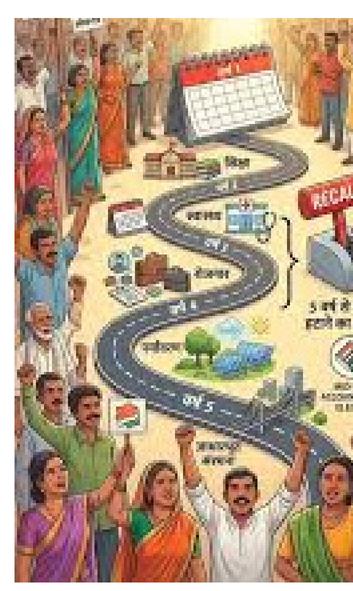

इसलिए हमारे प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी, जो लगातार चुनावी मोड में थे, इन ढाई महीनों में कटौती या मितव्ययिता का नाम तक नहीं ले सके, न ही उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाईं ताकि मतदाता नाराज न हों। भाजपा को भी चुनावों में इसका फायदा मिला। लेकिन इन फायदों के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था लगातार और भी कमजोर होती चली गई। नतीजतन, स्थिति अंततः इतनी बिगड़ गई कि पानी गर्दन तक बहने लगा, और हमारे प्रधानमंत्री ने जनता के लिए "संकल्प" घोषित करना शुरू कर दिया, जैसे मितव्ययी बनें, पेट्रोल बचाएं, डीजल बचाएं, सोना न खरीदें, तेल का उपयोग कम करें आदि। लेकिन सवाल यह है कि इन "संकल्पों" को लागू करने में इतना समय क्यों लगा? चुनावी लाभ के लिए देश की अर्थव्यवस्था को इस तरह से नुकसान पहुंचाना किस तरह की नीति है?

प्रधानमंत्री ने ढाई महीने बाद भी जनता से जिन मितव्ययिता उपायों की बात की है, उन्हें शुरू में लागू क्यों नहीं किया? इतना ही नहीं, क्या इन मितव्ययिता उपायों या प्रस्तावों को लागू करने का दायित्व केवल जनता का है? उन नेताओं या बाबुओं का नहीं जो सरकार के लाभ उठाते हैं?

वैश्विक संकट के समय में, जनता को मितव्ययी होना चाहिए और अपने नागरिक कर्तव्यों का शत प्रतिशत निर्वाह करना चाहिए, लेकिन नेताओं और अधिकारियों को पहले इसे लागू करना होगा। जो कि फिलहाल होता हुआ प्रतीत नहीं होता।

अंजनाद्री पहाड़ी मंदिर में 2.5 करोड़ रुपये के दान में सोने के बजाय तांबे के आभूषण मिलने से विवाद और गहरा गया है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। भगवान हनुमान की जन्मभूमि माने जाने वाले प्रसिद्ध अंजनाद्री पहाड़ी मंदिर में दिए गए दान को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि आधिकारिक सत्यापन के दौरान 2.5 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण सोने की परत चढ़े तांबे के आभूषण पाए गए हैं।

यह घटना तब सामने आई जब हैदराबाद के उद्योगपति महेश रेड्डी ने 8 मई को मंदिर में एक सजावटी मुकुट, एक चक्र और एक गदा दान की। उद्योगपति ने गंगावती विधायक गली जनार्दन रेड्डी के साथ मंदिर का दौरा किया था, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनके एक करीबी सहयोगी ने देवता को लगभग 2.5 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण दान किए हैं।

हालांकि, सरकारी खजाने में आभूषणों को आधिकारिक रूप से स्वीकार करने से पहले, जिला अधिकारियों को अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। सहायक आयुक्त महेश मालागीती के नेतृत्व में किए गए निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने बताया कि आभूषणों में से केवल 28 ग्राम ही असली सोना था। शेष भाग कथित तौर पर तांबे के बने थे जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि व्यापारी आभूषणों की आधिकारिक खरीद रसीद या प्रामाणिकता संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत करने में विफल रहा। सूत्रों के अनुसार, दानकर्ता के अनुरोध पर इन आभूषणों का उपयोग देवता को केवल दो दिनों के लिए सुशोभित करने के लिए किया गया था।

इस खुलासे के बाद, जिला प्रशासन ने महेश रेड्डी को नोटिस जारी कर आभूषणों के वैध बिल और वास्तविक मूल्य का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। अधिकारियों ने उचित दस्तावेज जमा होने तक दान की गई वस्तुओं को सरकारी खजाने में जमा करने से भी इनकार कर दिया है। इस घटना ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच व्यापक बहस छेड़ दी है। इससे धार्मिक दान के नाम पर प्रसिद्धि हासिल करने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि मंदिर की पवित्रता की रक्षा करना और दान में पारदर्शिता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है।

सोना वायदा में 9228 रुपये और चांदी वायदा में 18897 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा में 33 रुपये का सुधार

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 413077.96 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 63275.91 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 349802.05 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 4881.23 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 51316.24 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 154851 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 164497 रुपये और नीचे में 154851 रुपये पर पहुंचकर, 153442 रुपये के पिछले बंद के सामने 9228 रुपये या 6.01 फीसदी की तेजी के संग 162670 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी मई वायदा 7072 रुपये या 5.74 फीसदी की तेजी के संग 130209 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल मई वायदा 861 रुपये या 5.58 फीसदी की तेजी के संग 16292 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी जून वायदा सत्र के आरंभ में 153575 रुपये के भाव पर खूलकर, 163576 रुपये के दिन के उच्च और 153230 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 8739 रुपये या 5.71 फीसदी की तेजी के संग 161885 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 154083 रुपये के भाव पर खूलकर, 163475 रुपये के दिन के उच्च और 154083 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 153442 रुपये के पिछले बंद के सामने 8615 रुपये या 5.61 फीसदी की तेजी के संग 162057 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा सत्र के आरंभ में 290224 रुपये के भाव पर खूलकर, 301429 रुपये के दिन के उच्च और 290224 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 279062 रुपये के पिछले बंद के सामने 18897 रुपये या 6.77 फीसदी की तेजी के संग 297959 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 19051 रुपये या 6.79 फीसदी की तेजी के संग 299609 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 19040 रुपये या 6.79 फीसदी की तेजी के संग 299600 रुपये प्रति किलो हुआ।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 63275.91 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 349802.05 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 51316.24 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

मेटल वर्ग में 7268.83 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 16.05 रुपये या 1.15 फीसदी बढ़कर 1406.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मई वायदा 1.65 रुपये या 0.46 फीसदी की तेजी के संग 364 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 8.3 रुपये या 2.2 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 386.3 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मई वायदा 1.25 रुपये या 0.61 फीसदी की तेजी के संग 204.6 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 4565.84 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 9673 रुपये के भाव पर खूलकर, 9807 रुपये के दिन के उच्च और 9614 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 33 रुपये या 0.34 फीसदी की बढ़त के साथ 9756 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा 35 रुपये या 0.36 फीसदी की मजबूती के साथ 9758 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा 270.6 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 274 रुपये और नीचे में 269.6 रुपये पर पहुंचकर, 270.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 1.3 रुपये या 0.48 फीसदी बढ़कर 272.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 1.4 रुपये या 0.52 फीसदी की तेजी के संग 272.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 1020 रुपये के भाव पर खूलकर, 2 रुपये या 0.2 फीसदी की गिरावट के साथ 995 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 32720.46 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 18595.78 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 5797.66 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 921.09 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 30.24 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 509.50 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 2824.78 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1720.54 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 5.10 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 11570 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 64503 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 21825 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 278269 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 43418 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8615 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 22238 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 70136 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17861 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 26923 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मई 9700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 30.8 रुपये की गिरावट के साथ 186 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 60 पैसे के सुधार के साथ 11.05 रुपये हुआ।

सोना मई 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 232 रुपये की बढ़त के साथ 310 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 350000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1011 रुपये की बढ़त के साथ 1764 रुपये हुआ। तांबा मई 1500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.91 रुपये की बढ़त के साथ 6.7 रुपये हुआ। जस्ता मई 410 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.54 रुपये की बढ़त के साथ 1.55 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मई 9700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 61.8 रुपये की गिरावट के साथ 133.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 70 पैसे की नरमी के साथ 9.1 रुपये हुआ। सोना मई 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 954.5 रुपये की गिरावट के साथ 461.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 825.5 रुपये की गिरावट के साथ 980 रुपये हुआ। तांबा मई 1400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 7.42 रुपये की गिरावट के साथ 25.1 रुपये हुआ। जस्ता मई 357.5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4.78 रुपये की गिरावट के साथ 0.11 रुपये हुआ।

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन द्वारा मई दिवस के अवसर पर रेलवे कर्मचारियों का सम्मान

समर्पित सेवा के लिए 38 व्यक्तिगत पुरस्कार एवं एक समूह नकद पुरस्कार प्रदान किए गए

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) की अध्यक्षा श्रीमती सुजाता पाण्डेय कार्यकारी समिति की सदस्याओं के साथ पश्चिम रेलवे मुख्यालय में आयोजित मई दिवस समारोह के दौरान पुरस्कार विजेता कर्मचारी को सम्मानित करते हुए।

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) द्वारा मई दिवस के अवसर पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम रेलवे पर रेल सेवाओं के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने हेतु निष्ठा एवं अथक परिश्रम से कठिन दायित्व निभाने वाले रेलवे कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम विभिन्न विभागों के उन कर्मचारियों के समर्पण एवं प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जो यात्रियों की सुविधा तथा रेलवे परिचालन के हित में निरंतर कार्यरत हैं।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती सुजाता पाण्डेय ने कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ पश्चिम रेलवे के विभिन्न मंडलों, कारखानों एवं विभागों के कर्मचारियों को समारोह के दौरान सम्मानित किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट योगदान एवं समर्पित सेवा के लिए कुल 38 व्यक्तिगत पुरस्कार तथा एक समूह नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों को पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन द्वारा मेरिट प्रमाणपत्र एवं उपहार भेंट किए गए।

श्रीमती सुजाता पाण्डेय ने समारोह को संबोधित करते हुए कर्मचारियों के ईमानदार प्रयासों, अनुशासन एवं समर्पण की सराहना की, जो चुनौतीपूर्ण एवं गतिशील कार्य परिस्थितियों के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारियों की प्रतिबद्धता एवं कठिन परिश्रम निर्बाध रेल सेवाओं को बनाए रखने तथा यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय सेवाएं प्रदान कर रही महिला कर्मचारियों के महत्वपूर्ण योगदान की भी प्रशंसा की।

श्रीमती पाण्डेय ने आगे कहा कि समर्पित सेवा के इस प्रकार के सम्मान युवा कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत एवं उत्कृष्टता का मानदंड सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कार्य करने वाले कर्मचारियों का सम्मान करने से उनका मनोबल बढ़ता है तथा अन्य कर्मचारियों को भी अपने कर्तव्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलती है।

इस अवसर पर श्रीमती पाण्डेय ने आगामी छह महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को स्वस्थ, सुखद एवं आनंदमय सेवानिवृत्त जीवन के लिए शुभकामनाएं भी दीं तथा वर्षों से पश्चिम रेलवे की प्रगति एवं विकास में उनके बहुमूल्य योगदान की सराहना की।

भारत की पहली Semi High-Speed Rail Project को मिली मंजूरी, कैबिनेट ने अहमदाबाद–धोलेरा सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन रेलवे परियोजना को दी मंजूरी

20,667 करोड़ की लागत से विकसित होगी भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना

नई दिल्ली / अहमदाबाद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने आज रेल मंत्रालय की अहमदाबाद (सरखेज) – धोलेरा सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन रेलवे परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी। लगभग 20,667 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी तकनीक आधारित सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना होगी।

करीब 134 किलोमीटर लंबी यह नई रेलवे लाइन अहमदाबाद, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (SIR), आगामी धोलेरा एयरपोर्ट तथा लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (National Maritime Heritage Complex) को अत्याधुनिक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। परियोजना के पूर्ण होने के बाद अहमदाबाद और धोलेरा के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे यात्रियों के लिए दैनिक आवागमन और एक ही दिन में आने-जाने की सुविधा अधिक सहज एवं आरामदायक बनेगी।

रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw ने इस ऐतिहासिक निर्णय पर कहा:

"अहमदाबाद–धोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना भारत के रेलवे इतिहास में एक नई शुरुआत है। यह केवल एक रेल लाइन नहीं, बल्कि 'न्यू इंडिया' की आधुनिक, तेज और आत्मनिर्भर परिवहन व्यवस्था का प्रतीक है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित यह परियोजना आने वाले वर्षों में देशभर में सेमी हाई-स्पीड रेल नेटवर्क विस्तार का आधार बनेगी।"

अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) वेद प्रकाश ने कहा कि यह परियोजना गुजरात के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को नई गति देगी। उन्होंने कहा: "यह परियोजना अहमदाबाद एवं धोलेरा क्षेत्र को विश्वस्तरीय रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित एवं आधुनिक यात्रा सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र में रोजगार, उद्योग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी बड़ा लाभ होगा। इस इस परियोजना से धोलेरा और अहमदाबाद की दूरी 1 घंटे से भी काम हो जाएगी और धोलेरा सीधे अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जुड़ जाएगी।

परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी एवं लॉजिस्टिक दक्षता को मजबूत करना है। इस परियोजना से लगभग 284 गांवों एवं लगभग 5 लाख आबादी को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

भारतीय रेलवे के अनुसार यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। इससे लगभग 0.48 करोड़ लीटर तेल की बचत होगी तथा लगभग 2 करोड़ किलोग्राम CO उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 10 लाख पेड़ों के रोपण के बराबर पर्यावरणीय लाभ के समान है।

परियोजना को वर्ष 2030-31 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भावनगर मंडल के सतर्क लोको पायलट ने 6 सिंहों के झुंड को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया

पश्चिम रेलवे के भावनगर रेलवे मंडल द्वारा एशियाई सिंहों एवं अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। मंडल प्रशासन के निर्देशानुसार लोको पायलट निर्धारित गति सीमा का पालन करते हुए अत्यंत सतर्कता के साथ ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं। लोको पायलटों की सजगता तथा वन विभाग के फॉरेस्ट ट्रैकरों के साथ समन्वित कार्यवाही के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 159, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 129 तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल माह से अब तक 11 सिंहों को सुरक्षित बचाया जा चुका है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 12 मई 2026 (मंगलवार) को लोको पायलट श्री रमेश पी. (मुख्यालय-जूनागढ़) तथा सहायक लोको पायलट श्री चिंतन कुमार (मुख्यालय-जूनागढ़) ट्रेन संख्या 52946 जूनागढ़–वेरावल पैसेंजर का संचालन कर रहे थे। इस दौरान जूनागढ़–विसावदर रेलखंड में किलोमीटर संख्या 05/01 के निकट रेलवे ट्रैक पर अचानक 6 सिंहों का एक झुंड पटरी पार करता दिखाई दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लोको पायलट ने तत्काल सूझबूझ एवं तत्परता का परिचय देते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को सुरक्षित रूप से रोक दिया, जिससे सभी सिंह संभावित दुर्घटना से बच गए।

इसके पश्चात लोको पायलट द्वारा ट्रेन मैनेजर (गार्ड) श्री ललन कुमार (मुख्यालय-जूनागढ़) को तत्काल सूचना दी गई। वन विभाग के फॉरेस्ट ट्रैकर ने मौके पर पहुंचकर सभी सिंहों को सुरक्षित रूप से रेलवे ट्रैक से हटाया। स्थिति सामान्य होने के उपरांत लोको पायलट को ट्रेन के पुनः प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई तथा ट्रेन को सावधानीपूर्वक गंतव्य की ओर रवाना किया गया।

इस घटना की जानकारी प्राप्त होने पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा सहित मंडल के अन्य अधिकारियों ने लोको पायलटों की सतर्कता, संवेदनशीलता एवं कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की।

भावनगर मंडल वन्यजीव संरक्षण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा रेलवे एवं वन विभाग के समन्वित प्रयासों से एशियाई सिंहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा।

पुरी स्टेशन पर ब्लॉक के चलते गांधीधाम-पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस आंशिक निरस्त

पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के पुरी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म अपग्रेडेशन कार्य के लिए ब्लॉक लिया गया है। जिसके कारण गांधीधाम-पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेनें आंशिक निरस्त रहेगी। विवरण निम्नानुसार है:

आंशिक निरस्त ट्रेनें

- 15,22 एवं 29 मई 2026 की ट्रेन संख्या 12993 गांधीधाम–पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।
- 18 एवं 25 मई 2026 की ट्रेन संख्या 12994 पुरी–गांधीधाम एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।
- 20 एवं 27 मई 2026 की ट्रेन संख्या 22973 गांधीधाम–पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।
- 23 एवं 30 मई 2026 की ट्रेन संख्या 22974 पुरी–गांधीधाम एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।

यात्रियों से अनुरोध है उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। ट्रेन के परिचालन समय, ठहराव एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की अधिकृत वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की गुजरात को विशिष्ट भेंट

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद-धोलेरा सेमी हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया
- भारत का पहला सेमी हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट गुजरात को मिलना पूरे राज्य के लिए गौरव की बात : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
- धोलेरा एसआईआर, निर्माणाधीन धोलेरा एयरपोर्ट और लोथल राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के बीच तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले इस बहुआयामी प्रोजेक्ट से ईंधन की बचत होगी तथा कार्बन उत्सर्जन और लॉजिस्टिक्स खर्च में कमी आएगी

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत वाले अहमदाबाद के सरखेज से धोलेरा तक सेमी हाईस्पीड डबल लाइन रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात को पीएम-गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत तैयार किए गए इस विशिष्ट प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण विकासोन्मुखी भेंट देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना को साकार करने वाला और स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित भारतीय रेलवे का यह प्रथम सेमी हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट अहमदाबाद, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर), निर्माणाधीन धोलेरा एयरपोर्ट और लोथल राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के बीच तेज कनेक्टिविटी देने वाला एक बहुआयामी प्रोजेक्ट होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का पहला सेमी हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट गुजरात को मिलना पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री के विजन से शुरू होने वाला यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गुजरात के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। देश के पहले सेमी हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट के रूप में, यह प्रोजेक्ट सेमी हाईस्पीड रेल के चरणबद्ध विस्तार के लिए एक संदर्भ मॉडल के रूप में काम करने वाले एक अग्रणी प्रोजेक्ट के रूप में सेवाएं देगा।

केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए इस प्रोजेक्ट में एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह प्रोजेक्ट लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा।

यह प्रस्तावित प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 134 किमी की वृद्धि करेगा। इसके अलावा, 284 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे लगभग 5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

इतना ही नहीं, पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा दक्ष परिवहन व्यवस्था के हिस्से के रूप में यह प्रोजेक्ट ईंधन बचाएगा तथा कार्बन उत्सर्जन और लॉजिस्टिक्स खर्च को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

भीषण गर्मी में यात्रियों को राहत: भावनगर मंडल के नवागढ स्टेशन पर नि :शुल्क शीतल पेयजल का वितरण

भीषण गर्मी एवं बढ़ते तापमान के मद्देनज़र यात्रियों को राहत प्रदान करने हेतु पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा जनहित में विशेष पहल की गई है। इस क्रम में दिनांक 13 मई, 2026 (बुधवार) को नवागढ रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए निःशुल्क शीतल पेयजल वितरण की व्यवस्था की गई।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि नवागढ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्षेत्र में यात्रियों को निःशुल्क शीतल पेयजल उपलब्ध कराया गया, जिससे उन्हें भीषण गर्मी से काफी राहत मिली।

निःशुल्क शीतल पेयजल वितरण में "मोजिला गणेश बापा ग्रुप-जेतपुर" का सहयोग रहा। इस संस्था के सदस्यों द्वारा यात्रियों के बीच 1000 ठंडा पानी की बोतल वितरित की गई। स्टेशन पर इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित करने में भावनगर मंडल के वाणिज्य विभाग के निरीक्षकों, टिकट चेकिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई तथा वितरण कार्य को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न किया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री दिनेश वर्मा ने कहा, "भीषण गर्मी के दौरान यात्रियों को राहत प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भावनगर मंडल द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से इस प्रकार की जनहितकारी गतिविधियाँ निरंतर आयोजित की जा रही हैं। यह पहल हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता एवं यात्री-हित के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है।"

भावनगर मंडल द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं मानवीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती रहें। भीषण गर्मी के दौरान इस प्रकार की राहत सेवाएँ आगे भी निरंतर जारी रहेंगी।

महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय द्वारा प्रतापनगर–एकतानगर खंड एवं वडोदरा तथा प्रतापनगर स्टेशन का निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय द्वारा आज प्रतापनगर–एकतानगर खंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया गया। महाप्रबंधक श्री पाण्डेय ने वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके एवं मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वडोदरा एवं प्रतापनगर स्टेशन का निरीक्षण भी किया।

महाप्रबंधक श्री पाण्डेय ने मंडल रेल प्रबंधक वडोदरा मंडल श्री राजू भडके तथा RLDA एवं NHSRCL के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वडोदरा स्टेशन का दौरा किया। मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने उन्हें यार्ड रीमॉडलिंग परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अवसंरचना कार्यों के बारे में जानकारी दी, जिसमें लाइन संख्या 6 एवं 7 को मुख्य लाइन से सीधे जोड़ने की व्यवस्था, प्लेटफॉर्म संख्या 4 एवं 5 की क्षमता में वृद्धि, एक नई स्टेबलिंग लाइन का विकास तथा अन्य संबंधित कार्य शामिल हैं। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के उन्नयन के अंतर्गत डिलांज का उद्घाटन भी किया गया।

महाप्रबंधक ने वडोदरा स्थित इलेक्ट्रिक लोको शेड का निरीक्षण मंडल प्रबंधक तथा मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया, निरीक्षण के दौरान उन्हें इलेक्ट्रिक लोको शेड में किए गए संशोधनों एवं भविष्य की विस्तार योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, अपने दौरे के दौरान उन्होंने शेड के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया, जिसमें न्यूमैटिक सेक्शन, ऑक्सिलियरी मोटर सेक्शन तथा बोगी सेक्शन शामिल हैं।

उन्हें लोको विफलताओं को शून्य करने के उद्देश्य से किए जा रहे तकनीकी विश्लेषण एवं अपनाए जा रहे सुधारात्मक उपायों के संबंध में भी अवगत कराया गया। इसके बाद महाप्रबंधक ने शेड में विकसित इन-हाउस ड्यूल मोड शंटिंग इंजन 'सारथी' का निरीक्षण किया तथा लोको शेड द्वारा की गई इस पहल की सराहना की। यह शंटिंग इंजन ओएचई तथा बैटरी — दोनों मोड में कार्य करने में सक्षम है, जिससे शंटिंग कार्यों में सुगमता, समय की बचत तथा 2–3 लोकोमोटिवों की कैस्केडिंग की आवश्यकता समाप्त होने जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। उन्हें इलेक्ट्रिक लोको शेड में स्थापित रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी गई।

निरीक्षण के अगले चरण में महाप्रबंधक ने प्रतापनगर रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन पर यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं, स्टेशन विकास कार्यों, यार्ड लेआउट तथा निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज की प्रगति का जायजा लिया और कार्यों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इसके बाद उन्होंने प्रतापनगर रेलवे कॉलोनी स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नव निर्मित पिकलबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया।

प्रतापनगर - एकतानगर खंड के विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण के बाद एकता नगर स्टेशन पर पहुंचने पर वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने महाप्रबंधक को स्टेच्यू आफ यूनिटी आने वाले पर्यटकों के लिए एकतानगर स्टेशन को और विकसित करने की योजना से अवगत कराया। ट्रेन परिचालन क्षमता को विस्तार देते हुए एकता नगर स्टेशन पर एक अतिरिक्त लूप लाइन का निर्माण प्रस्तावित है तथा नान फेयर रिवेन्यू के तहत फूड प्लाजा प्रस्तावित है।

एकतानगर स्टेशन से अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन के लिए लाइन क्षमता बढ़ाने हेतु प्रतापनगर - एकतानगर खंड के तिलकवाड़ा और मोरया स्टेशन को अपग्रेड किया गया है। प्रतापनगर - एकतानगर रेल खंड में ट्रेनों की पंक्चुअलिटी में सुधार हेतु मेटलफेंसिंग भी लगाई गई है।

गुजरात में टेंडर कोकोनट का उत्पादन पिछले दो वर्ष में 20 प्रतिशत बढ़ा, राज्य में वार्षिक 26 करोड़ नारियल का उत्पादन होता है

- गुजरात सरकार के प्रोत्साहन तथा जागरूकता कार्यक्रमों से राज्य में खेती की तसवीर बदली
- गिर के युवा किसान दिनेश सोलंकी ने अनूठे प्रयोग से नारियल उत्पादन में अनेक गुना वृद्धि की, आय 12-15 लाख रुपए तक पहुँची

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का कृषि क्षेत्र परंपरागत खेती से आधुनिक, टेक्नोलॉजी आधारित तथा निर्यातोन्मुखी खेती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुजरात में भी परंपरागत फसलों के अलावा बागवानी फसलों तथा मूल्यवर्धित खेती को निरंतर प्रोत्साहन मिलने से किसानों की आय बढ़ी है। राज्य का विशाल समुद्री तट नारियल की खेती के लिए अनुकूल होने के कारण उसका सीधा लाभ किसानों को मिलता है। टेंडर कोकोनट की बढ़ती मांग तथा समुद्री तट के विस्तार के कारण गुजरात ने नारियल की खेती में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज कराया है।

गुजरात में पिछले 2 वर्ष में टेंडर कोकोनट का उत्पादन लगभग 20 प्रतिशत बढ़ा

पिछले 2 वर्ष में राज्य में टेंडर कोकोनट के उत्पादन में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज किसान वार्षिक लगभग 26 करोड़ नारियल का उत्पादन करते हैं। यह आँकड़ा दर्शाता है कि गुजरात बागवानी क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। राज्य के लगभग 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नारियल की खेती की जाती है; जिसमें गिर सोमनाथ, जूनागढ, भावनगर, वलसाड, नवसारी, कच्छ तथा देवभूमि द्वारका जिलों का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2024-25 के आँकड़ों के अनुसार राज्य में टेंडर कोकोनट की औसत उत्पादकता लगभग 9.26 हजार प्रति हेक्टेयर है।

किसानों को राज्य सरकार दे रही है 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी

राज्य के किसान बागवानी फसलों तथा मूल्यवर्धन की ओर मुड़ें; इसके लिए गुजरात सरकार के बागवानी विभाग द्वारा प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही; किसानों पर आर्थिक बोझ न आए; इसके लिए नारियल की बुवाई पर सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके अतिरिक्त; मल्चिंग तथा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जैसी पद्धतियों के उपयोग से फसल की उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिले; इस उद्देश्य से उसमें भी सहायता दी जाती है। इसी प्रकार; बागवानी विभाग के अधीनस्थ नर्सरी से नारियल की ऊँची किस्म, वामन किस्म तथा हाइब्रिड किस्मों के अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे मिल जाते हैं और गुजरात ग्रीन रिवॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा टपक सिंचाई पद्धति में सहायता दी जाती है।

नारियल के लिए हानिकारक रगोस व्हाइटफ्लाई का नाश करने के लिए गिर के किसान ने अनूठा प्रयोग किया

चोरवाड से उना तक का समुद्र तटवर्ती क्षेत्र 'लीली नाघेर' (हरियाले क्षेत्र) के रूप में जाना जाता है, जहाँ पिछले दो वर्ष में रोगस व्हाइटफ्लाई (रोगस सफेद मक्खी) के प्रकोप से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यद्यपि; गुजरात सरकार के मार्गदर्शन व किसानों के प्रयासों से स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। गिर सोमनाथ जिले के सूत्रापाडा के युवा किसान दिनेश सोलंकी ने इस समस्या के निवारण के लिए देसी उपाय आजमाकर नारियल के उत्पादन के साथ अपनी आय में भी वृद्धि की है। उन्होंने 1000 लीटर पानी में गुड़ तथा गिर गाय के दूध का मिश्रण करके व्हाइटफ्लाई को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की है।

पहले उनके खेत में वर्ष में केवल 1,000 से 1,500 नारियल का उत्पादन होता था, परंतु इस प्रयोग के बाद यह उत्पादन बढ़कर वार्षिक 8,000 से 10,000 नारियल के करीब दर्ज हुआ है। आज उनकी वार्षिक आय 12 से 15 लाख रुपए तक पहुँची है और उनकी सफलता देखकर अन्य किसान भी यह पद्धति अपनाने को प्रेरित हुए हैं।

नारियल की खेती का क्षेत्र 70,000 हेक्टेयर तक बढ़ाने का गुजरात सरकार का लक्ष्य

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार का आगामी वर्षों में नारियल बुवाई क्षेत्र 70,000 हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। साथ ही; वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोकोनट पाउडर जैसे नारियल आधारित उत्पादों तथा प्रोसेसिंग द्वारा उनके मूल्यवर्धन एवं निर्यात बाजारों में प्रवेश के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। इसके चलते गुजरात आगामी समय में नारियल आधारित उद्योगों के वैश्विक हब के रूप में उभर आएगा।